उत्तर प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार कोल इंडिया लि० द्वारा अभी तक उत्तर प्रदेश में कोई थोक बिक्री डीलर की नियुक्ति नहीं की है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक उपरोक्त योजना के अंतर्गत थोक बिक्री डीलरों के रूप में नियुक्ति प्राप्त किए जाने के हकदार हैं, बशर्ते कि वे योजना में दी गई वाणिज्यिक शर्तों को पूरा करते हों।

देश में कोयला खानें

27. श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितनी कोयला खानें हैं ;

(ख) इन खानों में इस समय कितने लोग कार्यरत हैं; और

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान इन खानों से प्रति वर्ष कितनी मात्रा में कोयला निकाला गया ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि० तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० की कोयला खानों की कुल संख्या तथा इन खानों में कार्यरत कार्मिकों की संख्या नीचे दी गई है :–

कंपनी का नाम	खानों की सं०	1–4–93 की स्थिति के अनुसार कार्यरत कामगारों की संख्या
1. कोल इंडिया लि०	451	5,56,342
2. सिंगरेनी कोलियरीज कं० लि० . .	65	1,15,025

(ग) पिछले 5 वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि० तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० की कोयला खानों में उत्पादित कोयले की वर्ष-वार मात्रा नीचे दी गई है :–

(आंकड़े मि० टन में)

वर्ष	कोल इंडिया लि०	सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि०
1988–89	171.50	18.61
1989–90	178.60	17.80
1990–91	189.68	17.71
1991–92	204.14	20.58
1992–93*	211.22	22.60

*आंकड़े अनन्तिम

गुजरात में उद्योगों के लिये स्टीम कोयले की पूर्ति

28. श्री राम सिंह राठवा :
श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गुजरात में उद्योगों को पूर्ति के लिए चालू वर्ष अर्थात् 1993–94 के वर्ष के दौरान जिला-वार स्टीम कोयले की कितनी मात्रा का आवंटन किया है;

(ख) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य में उद्योग के लिए जिला-वार मंजूर किए गए स्टीम कोयला उनके लिए स्वीकृत मात्रा के अनुरूप आवंटन नहीं किया जाता है और इस संबंध

में उनकी शिकायतों को नजर-अन्दाज कर दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या ठोस कदम उठा रही है और क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(घ) क्या सरकार ने इसकी कम आपूर्ति के कारण औद्योगिक उत्पादन में जिला-वार आई भारी कमी पर ध्यान दिया है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्देश जारी किए हैं; और

(च) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (च) गजरात में औद्योगिक उपभोक्ताओं की स्टीम कोयले की आपूर्ति साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० तथा वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० द्वारा संबंधित प्रायोजन अधिकारियों द्वारा जारी प्रायोजन के आधार पर अधिकांशत: रेल द्वारा की जाती है। स्टीम कोयले के लिए यह ऐसे प्रायोजन रेलवे द्वारा नियत निर्धारित सीमा के भीतर रखा जाता है जो कि गुजरात राज्य के लिए 1102 वाक्स वैगन प्रति माह है। स्टीम कोयले का जिलावार आबंटन राज्य के प्रायोजन अधिकारियों द्वारा किया जाता है जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले के विभिन्न अधिकारियों द्वारा किया जाता है जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले के विभिन्न उपभोक्ता आते हैं। कोयला कंपनियों द्वारा कोयले के आवंटन तथा आपूर्ति के जिलावार आंकड़ों का हिसाब नहीं रखा जाता है।

राज्य को स्टीम कोयले की वास्तविक आपूर्ति स्टीम कोयले तथा रेलवे वैगन दोनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। गुजरात में अधिकांश उपभोक्ता साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की कोरिया-रेवा कोलफील्ड्स से कोयले की आपूर्ति को तरजीह देते हैं जहां से कोयले के प्रेषण को विभिन्न अवरोधों के कारण, जिनमें परिवहन भी शामिल है, बढ़ाया नहीं जा सका है। इसके अलावा, विद्युत, स्टील तथा सीमेंट जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को रेल द्वारा कोयले के संचलन में प्राथमिकता दिए जाने के कारण भी औद्योगिक उपभोक्ताओं के कोयले के संचलन में कुछ कमी आई है जिससे इन यूनिटों का उत्पादन प्रभावित हुआ है।

किन्तु, कोयला कंपनियों को परामर्श दिया गया है कि वे उपभोक्ता क्षेत्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप कोयले की आपूर्ति में वृद्धि करे। गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को यह सुविधा दी गई है कि वे रेल द्वारा कम आपूर्ति किए जाने के एवज में विनिर्दिष्ट स्रोतों से सड़क मार्ग द्वारा कोयला उठा सकते हैं। अनेक कोलियरियों को उदारीकृत बिक्री योजना के अंतर्गत लाया गया है जहां से कि औद्योगिक उपभोक्ता बिना किसी प्रायोजन के अपनी जरूरत का कोयला उठा सकते हैं।

रेलवे वैगनों द्वारा कोयले की ढुलाई

29. श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे वैगनों की अनुपलब्धता के कारण कोयला की ढुलाई का कार्य भलीभांति नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयला कंपनियों की रेलवे वैगनों की कितनी मांग रही है और उस अवधि के दौरान उन्हें कितने रेलवे वैगन उपलब्ध कराए गए हैं; और

(ग) सरकार ने कोयला कंपनियों को पर्याप्त रेलवे वैगन उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रयास किए हैं?